30-05-2023

नीति आयोग का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21

समाचार पत्रों में क्यों?

नीति आयोग की 2020-21 की वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में केरल सबसे शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। केरल पिछले वर्षों में भी पहले स्थान पर आया था। तमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

त्वरित मुद्दा?

- रैंकिंग केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से 24 स्वास्थ्य संकेतकों के साथ एक समग्र स्कोरिंग प्रणाली पर आधारित है। नीति आयोग साल-दर-साल प्रगति और समग्र प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंक निर्धारित करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- रैंकों को 19 बड़े राज्यों, 8 छोटे राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
- 19 'बड़े राज्यों' में केरल पहला; तमिलनाडु दूसरा और तेलंगाना तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
- बिहार (19वाँ), उत्तर प्रदेश (18वां) और मध्य प्रदेश (17वां) सूची में अंतिम स्थान पर हैं।
- आठ छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन दर्ज किया है, इसके बाद सिक्किम और गोवा का स्थान है; अरुणाचल प्रदेश (6वाँ), नगालैंड (7वाँ) और मणिपुर (8वाँ) सूची में अंतिम स्थान पर हैं।
- आठ केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप को समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष

अन्य प्रमुख तथ्य?

नीति आयोग का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक की संरचना

- स्वास्थ्य सूचकांक एक समग्र स्कोर है जो तीन क्षेत्रों में 24 संकेतकों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की उपलब्धियों एवं वृद्धिशील सुधारों को दर्शाता है: स्वास्थ्य परिणाम, शासन व सूचना तथा प्रमुख इनपुट और प्रक्रियाएँ।
- 'स्वास्थ्य परिणामों' में नवजात मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव का अनुपात, तपेदिक के कुल मामलों की अधिसूचना दर और एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी पर HIV के साथ रहने वाले लोगों के अनुपात जैसे संकेतक शामिल हैं।
- 'शासन और सूचना' क्षेत्र में संस्थागत वितरण का अनुपात, राज्य स्तर पर तीन प्रमुख पदों की औसत अवधि (महीनों में), मुख्य चिकित्सा अधिकारी की औसत अवधि (महीनों में) और निधि स्थानांतरण में लगने वाले दिन जैसे संकेतक शामिल हैं।
- 'प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाएँ' उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का एक उपाय है, जिसमें कार्यात्मक 24X7 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, कार्यात्मक हृदय संबंधी देखभाल इकाइयों वाले ज़िलों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पदों में रिक्तियों का अनुपात शामिल है।

प्रदर्शनकर्त्ता के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।

- राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा वर्ष 2019-20 में अपने प्रदर्शन की तुलना में वर्ष 2020-21 में शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्त्ताओं के रूप में उभरे हैं
- वर्ष 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा विश्व बैंक के सहयोग से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र प्रदर्शन एवं वृद्धिशील प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिये एक वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक प्रारंभ किया।
- वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक का उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन पर प्रगति को ट्रैक करना और रैंक प्रदान करना तथा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करना एवं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य क्रॉस लर्निंग को प्रोत्साहित करना है।
- स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का दो मापदंडों पर आकलन करता है- वृद्धिशील प्रदर्शन (वर्ष-दर-वर्ष प्रगति) और समग्र प्रदर्शन।
- रैंकिंग तीन श्रेणियों के तहत की जाती है: समान संस्थाओं के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिये विशाल राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश।

संयुक्त कुपोषण अनुमान

समाचार पत्रों में क्यों?

यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक द्वारा जारी संयुक्त कुपोषण अनुमान (जेएमई) के अनुसार, वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों के अनुरूप, भारत ने स्टंटिंग में कमी जारी रखी है और 2012 की तुलना में 2022 में पांच साल से कम उम्र के स्टंटेड बच्चों की संख्या 1.6 करोड़ कम दर्ज की गई है।

त्वरित मुद्दा?

- हालांकि, वजन कम होना चिंता का विषय बना हुआ है और इसी तरह मोटापे का बढ़ता स्तर भी चिंता का विषय बना हुआ है।

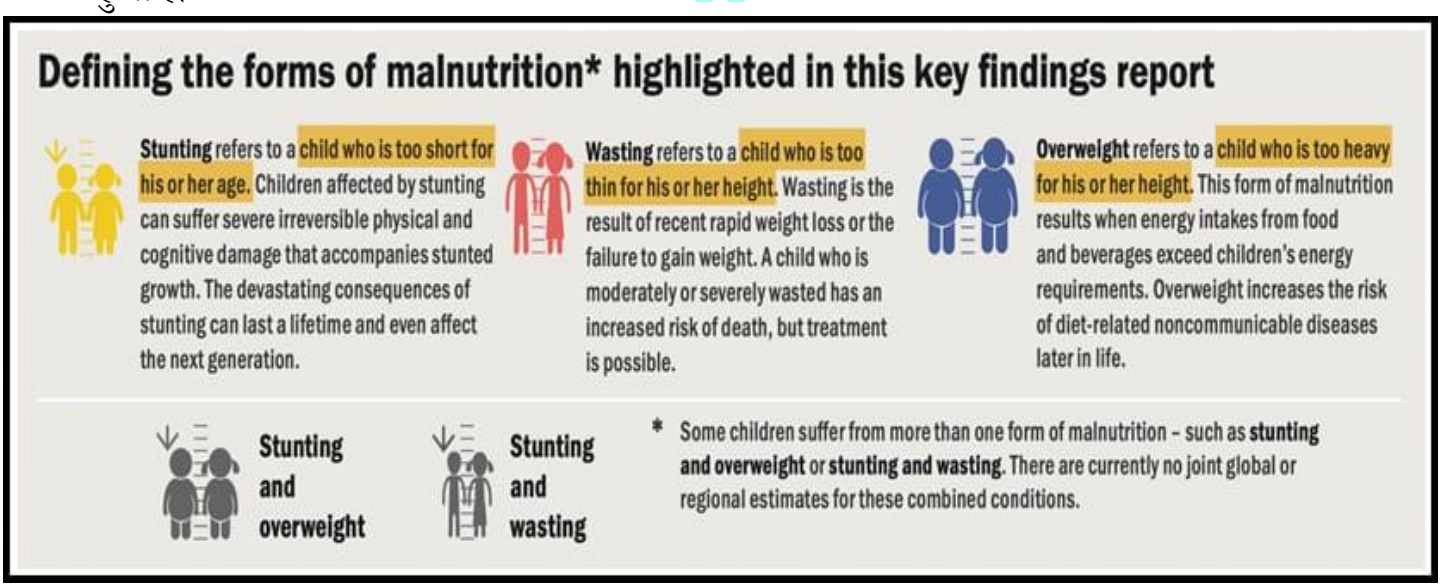

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग 2012 में 41.6% की व्यापकता दर से गिरकर 2022 में 31.7% हो गई - संख्या 52 लाख से घटकर 36 लाख हो गई। इसके साथ ही पिछले एक दशक में स्टंटिंग के वैश्विक बोझ में भारत की हिस्सेदारी 30% से घटकर 25% हो गई।
- मोटापे की व्यापकता एक दशक में 2012 में 2.2% से बढ़कर 2022 में 2.8% हो गई, जिसकी संख्या 27.5 लाख से बढ़कर 31.8 लाख हो गई, जिससे वैश्विक हिस्सेदारी में 8.8% का योगदान हुआ।
- वैश्विक स्तर पर, स्टंटिंग की व्यापकता दर 2012 में 26.3% से घटकर 2022 में 22.3% हो गई। दक्षिण एशिया में गिरावट बहुत तेज थी क्योंकि यह 40.3% से घटकर 30.5% हो गई।
- रिपोर्ट कहती है कि 2025 विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) वैश्विक पोषण लक्ष्य और 2030 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2 लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त प्रगति है।

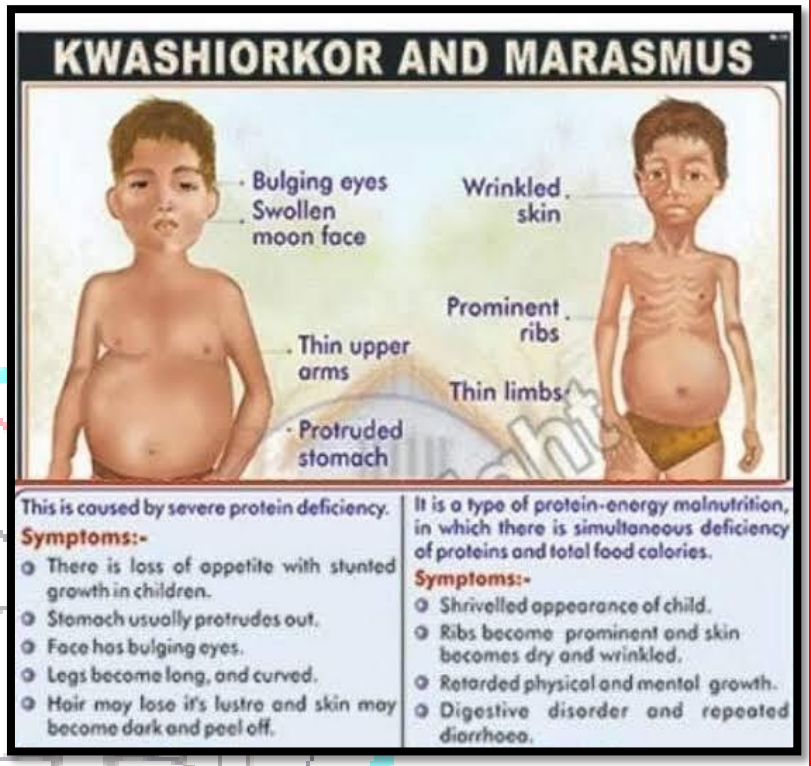

- स्टंटिंग: स्टंटिंग को कम ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह दीर्घकालिक या बार-बार होने वाले कुपोषण का परिणाम है, जो आमतौर पर गरीबी, खराब मातृ स्वास्थ्य और पोषण, बार-बार बीमारी और / या शुरुआती जीवन में अनुचित आहार और देखभाल से जुड़ा होता है।
- वेस्टिंग: वेस्टिंग को कद के अनुपात में कम वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है । यह अक्सर हाल ही में और गंभीर वजन घटाने का संकेत देता है, हालांकि यह लंबे समय तक भी बना रह सकता है।

दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021

समाचार पत्रों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की दुर्लभ बीमारियों की नीति को कुशल तरीके से लागू करने और रोगियों तक इसका लाभ सुनिश्चित करने के लिए पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

त्वरित मुद्दा?

- दिसंबर 2021 को, दिल्ली एचसी ने केंद्र से इस मामले को देखने का आग्रह किया था, जिसमें कहा गया था कि दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत पहचाने गए रोगियों को धन की कमी के कारण पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इस नीति के तहत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'दुर्लभ रोगों के रोगियों के लिए डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउडफंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशन' के साथ सैकड़ों रोगियों ज्यादातर बच्चों को पंजीकृत किया गया है।
- नीति में दुर्लभ बीमारियों की परिभाषा और देश के भीतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्धता हेतु दुर्लभ बीमारियों की एक राष्ट्रीय स्तर की अस्पताल आधारित रजिस्ट्री की परिकल्पना की गई है।

- स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों और जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केन्द्रों जैसी प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के माध्यम से त्वरित जांच और बचाव पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- नीति का उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान पर ज्यादा जोर के साथ दुर्लभ बीमारियों के उपचार की ऊंची लागत को कम करना है।
- नीति का अन्य उद्देश्य उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के रूप में वर्णित 8 स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से दुर्लभ के रूप में वर्णित है बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत बनाना भी है और इन केंद्रों को निदान सुविधाओं के सुधार के लिए 5 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- एकमुश्त उपचार (दुर्लभ रोग नीति में समूह 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारी) वाली दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए, राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छत्रक योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के वित्तीय समर्थन का प्रावधान है।
- इस वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थियों को बीपीएल परिवारों के अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र 40% आबादी तक बढ़ाया जाएगा।
- नीति में एक क्राउड फंडिंग व्यवस्था की भी कल्पनी की गई है, जिसमें कंपनियों और लोगों को आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

देश को मिला नया संसद भवन

समाचार पत्रों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई, 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ देश के नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया और नई लोकसभा के सदन में पवित्र सेंगोल (राजदंड) को श्रद्धा के साथ प्रतिष्ठित किया।

त्वरित मुद्दा?

- नया संसद भवन 65 हजार वर्ग मीटर में बना है। तिकोने आकार के कारण इसमें स्थान का अधिकतम उपयोग हुआ है। लोकसभा कक्ष में आठ सौ 88 सीटें हैं और इसकी विषय-वस्तु राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा कक्ष में तीन सौ 84 सीटें हैं और यह राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- नए संसद भवन में एक अद्वितीय त्रिकोणीय आकार है, जो परिसर के भीतर कुशल स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है। यह डिजाइन अधिकतम कार्यक्षमता की अनुमति देता है और बड़े विधायी कक्षों को समायोजित करता है।
- मोर थीम से प्रेरित, लोकसभा में बैठने की क्षमता बढ़ाई गई है। 888 सीटों के साथ, यह वर्तमान क्षमता का लगभग तीन गुने सदस्यों को समायोजित करेगा। लोकसभा हॉल संयुक्त सत्र के लिए 1,272 सीटों को समायोजित करने में भी सक्षम होगा।
- राष्ट्रीय पुष्प कमल थीम से से प्रेरित राज्यसभा में 384 सीटें हैं। सदन में पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने के लिए नई डिजाइन में राज्य सभा सदस्यों की संख्या में भविष्य में वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया है।

- नए संसद भवन में एक अलग से कॉम्प्लेक्स के केंद्र में स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है। नए संसद भवन में एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है, जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति, लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है।
- नए संसद भवन को भूकंप झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि दिल्ली अब जोन 4 में है, भूकंप के उच्च जोखिम की विशेषता है, जोन 5 तक के मजबूत झटके सहन करने के लिए नई संरचना को मजबूत किया गया है।
- नए संसद भवन की प्रत्येक सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगा लगाया गया है, जो संसद सदस्यों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यह वृद्धि विधायी अनुभव को बढ़ाएगी और संचार की सुविधा प्रदान करेगी।
- नया संसद भवन हरित निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाता है।
- इमारत में ऊर्जा बचत उपकरणों को शामिल किया गया है, जिससे बिजली की खपत में 30% की कमी आई है। वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को भी डिजाइन में शामिल किया गया है।